छह दिग्गज कंपनियों का बाजार मूल्य बढ़ा

88,678 करोड़ रुपये की बढ़त, आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा लाभार्थी

मुंबई, 28 जून बीते कारोबारी सप्ताह में देश की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से छह के बाजार पूंजीकरण में कुल 88,678.1 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस दौरान आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा लाभार्थी रहा, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में पहले स्थान पर कायम रही.

बीते कारोबारी सप्ताह में शेयर बाजार में सीमित कारोबार के बावजूद देश की प्रमुख कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली. शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से छह कंपनियों के संयुक्त बाजार मूल्य में 88,678.1 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ. इस तेजी का सबसे अधिक लाभ आईसीआईसीआई बैंक को मिला. आईसीआईसीआई बैंक का बाजार पूंजीकरण 29,588.75 करोड़ रुपये बढ़कर करीब 9.95 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, भारतीय स्टेट बैंक और लार्सन एंड टुब्रो के बाजार मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. इन कंपनियों के शेयरों में निवेशकों की खरीदारी से उनकी बाजार स्थिति और मजबूत हुई.=

दूसरी ओर, बाजार में तेजी के बावजूद चार प्रमुख कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में गिरावट आई. इनमें भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारतीय जीवन बीमा निगम और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल हैं.

> बाजार पूंजीकरण के आधार पर रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी हुई है. इसके बाद दूसरे स्थान पर एचडीएफसी बैंक, तीसरे पर भारती एयरटेल, चौथे पर आईसीआईसीआई बैंक और पांचवें स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक है. सूची में छठे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सातवें पर बजाज फाइनेंस, आठवें पर लार्सन एंड टुब्रो, नौवें पर भारतीय जीवन बीमा निगम तथा दसवें स्थान पर हिंदुस्तान यूनिलीवर है.

सोना-चांदी की कीमतों में फिर उछाल

नई दिल्ली, 28 जून. सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे बाजार में हल्की हलचल देखने को मिली. शादी-ब्याह और निवेश की योजना बनाने वाले खरीदारों के लिए आज का दिन अहम माना जा रहा है, क्योंकि सर्राफा बाजार में सोने के दाम ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे हैं. ताजा रेट के अनुसार 24 कैरेट सोना करीब 1,43,950 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,31,950 और 18 कैरेट सोना 1,07,960 के आसपास बना हुआ है. वहीं चांदी की कीमत भी मजबूत बनी हुई है और यह लगभग 2,40,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही है. देश के अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिला है, लेकिन कुल मिलाकर रुझान तेजी का ही है.

छह बड़े संकेत तय करेंगे बाजार चाल

व्यापार समझौता, कच्चा तेल और आर्थिक आंकड़ों पर रहेगी निवेशकों की नजर

नई दिल्ली, 28 जून. सोमवार से शुरू होने वाला कारोबारी सप्ताह भारतीय शेयर बाजार के लिए बेहद अहम रहने वाला है. भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की प्रगति, पश्चिम एशिया के तनाव, कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और देश के छह प्रमुख आर्थिक आंकड़ों के आधार पर बाजार की दिशा तय होगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें किसी भी मोर्चे पर निराशाजनक संकेत मिलने पर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है.

भारतीय शेयर बाजार के लिए नया कारोबारी सप्ताह कई बड़े घरेलू और वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से उतार-चढ़ाव भरा रहने की संभावना है. निवेशकों की निगाहें भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते, पश्चिम एशिया की स्थिति, कच्चे तेल की कीमतों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के रुख और देश के महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों पर टिकी रहेंगी.

> सबसे बड़ा सकारात्मक संकेत भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते को लेकर मिला है. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बैठक के बाद कहा कि दोनों देश एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब हैं. यदि यह समझौता होता है तो दोनों देशों के व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे और निर्यात आधारित उद्योगों को लाभ मिल सकता है. इसका सकारात्मक असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखाई दे सकता है.

अशोक वासवानी छोड़ेंगे कोटक बैंक की कमान

नई दिल्ली, 28 जून. कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अशोक वासवानी 31 दिसंबर 2026 को अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ देंगे. उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से दोबारा नियुक्ति नहीं लेने का फैसला किया है. बैंक के निदेशक मंडल ने उनके निर्णय को स्वीकार करते हुए नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

कोटक महिंद्रा बैंक में शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. बैंक ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि उसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक वासवानी वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपने पद पर बने नहीं रहेंगे. उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होगा.

बैंक के अनुसार, अशोक वासवानी ने व्यक्तिगत कारणों से दोबारा इस पद पर नियुक्ति नहीं लेने का निर्णय लिया है. उन्होंने अपने इस फैसले की जानकारी निदेशक मंडल को दे दी है. निदेशक मंडल ने बैठक में उनके निर्णय का सम्मान करते हुए उसे स्वीकार कर लिया और नए एमडी एवं सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया.

पाक विस्थापित महिलाओं की वैश्विक सफलता

नई दिल्ली, 28 जून. संघर्ष से शुरू हुई यह कहानी आज मेहनत, हुनर और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी है. राजस्थान के बाड़मेर जिले में रहने वाली पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों की महिलाएं आज अपनी पारंपरिक सूफ कढ़ाई के जरिए न सिर्फ अपनी पहचान बना रही हैं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार तक अपनी कला पहुंचा रही हैं. रंग-बिरंगे धागों, छोटे-छोटे शीशों और पारंपरिक ज्यामितीय डिजाइनों से तैयार की जाने वाली यह कढ़ाई पूरी तरह हाथ से की जाती है. इन महिलाओं द्वारा बनाए गए बैग, कुशन कवर, वॉल हैंगिंग, कपड़े, बेडशीट और सजावटी सामान अब भारत के बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोप के अन्य देशों में भी पसंद किए जा रहे हैं.

दस वर्षों में यूपीआई ने रचा इतिहास

लेन-देन 2 करोड़ से बढ़कर 24,162 करोड़

नई दिल्ली, 28 जून. देश में डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने पिछले दस वर्षों में अभूतपूर्व बदलाव देखा है. वर्ष 2016 में शुरू हुई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सेवा आज करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. वित्त वर्ष 2016-17 में जहां यूपीआई के जरिए केवल दो करोड़ लेनदेन हुए थे, वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक पहुंच गई है.

भारत में डिजिटल भुगतान का चेहरा बदलने वाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने एक दशक में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वित्त वर्ष 2016-17 में यूपीआई के माध्यम से केवल दो करोड़ लेनदेन हुए थे, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गया. यह वृद्धि देश में डिजिटल भुगतान को तेजी से मिली स्वीकार्यता को दर्शाती है.

यूपीआई को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने विकसित किया है. यह एक रीयल-टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जो मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से दो बैंक खातों के बीच कुछ ही सेकंड में धनराशि स्थानांतरित करने की सुविधा देती है.

इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लेनदेन के लिए बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड साझा करने की आवश्यकता नहीं होती.

> यूपीआई की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उपयोगकर्ता एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में एक से अधिक बैंक खातों को जोड़ सकते हैं. इससे अलग-अलग बैंकों के खातों का संचालन आसान हो जाता है. वर्तमान में भीम, फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे कई लोकप्रिय एप्लिकेशन यूपीआई सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं.

ईएमआई चूकने से पहले बैंक से बात करें

समय रहते संपर्क करने पर मिल सकती है राहत

जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बचाव संभव

नई दिल्ली, 28 जून यदि किसी कारणवश आप अपने ऋण की मासिक किस्त (ईएमआई) समय पर जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो चूक होने से पहले बैंक से संपर्क करना सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है. समय रहते बैंक को अपनी वित्तीय स्थिति बताने पर लोन पुनर्गठन, किस्तों में राहत या अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं, जिससे जुर्माना, खराब क्रेडिट स्कोर और कानूनी कार्रवाई जैसी परेशानियों से बचा जा सकता है.

बदलती आर्थिक परिस्थितियों, नौकरी छूटने, व्यापार में नुकसान या अचानक आए चिकित्सा खर्च जैसी वजहों से कई बार लोग समय पर अपनी ऋण की मासिक किस्त जमा नहीं कर पाते. ऐसी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि ईएमआई की नियत तिथि निकलने का इंतजार करने के बजाय पहले ही बैंक से संपर्क किया जाए. बैंक ग्राहक की स्थिति को समझते हुए कई प्रकार की राहत देने पर विचार कर सकते हैं.

बैंकों द्वारा दी जाने वाली सबसे प्रमुख सुविधा लोन पुनर्गठन है. इसके तहत ऋण की अवधि बढ़ा दी जाती है, जिससे हर महीने चुकाई जाने वाली किस्त कम हो जाती है. इससे ग्राहक पर तत्काल वित्तीय बोझ कम पड़ता है.

> कुछ विशेष परिस्थितियों में बैंक ईएमआई अवकाश भी प्रदान कर सकते हैं. इसके तहत कुछ महीनों तक किस्त जमा करने की छूट मिलती है. हालांकि इस अवधि के दौरान ऋण पर ब्याज जुड़ता रहता है, इसलिए बाद में कुल भुगतान राशि बढ़ सकती है. यदि ग्राहक का क्रेडिट स्कोर पहले की तुलना में बेहतर हो गया है और उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होने की संभावना है, तो वह बैंक से ब्याज दर कम करने का अनुरोध भी कर सकता है. ब्याज दर में कमी आने से मासिक किस्त और कुल ब्याज का बोझ घट सकता है.

ऑडिट रिपोर्ट नहीं, प्रमोटरों पर रेरा सख्त

25 हजार रुपये लेट फीस और पांच फीसदी तक जुर्माने की चेतावनी

लखनऊ, 28 जून. उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी-रेरा) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा नहीं करने वाले 76 रियल एस्टेट परियोजनाओं के प्रमोटरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है.

प्राधिकरण ने सभी डिफॉल्टर प्रमोटरों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है. समयसीमा का पालन नहीं करने पर 25 हजार रुपये की लेट फीस के साथ परियोजना लागत के पांच प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. प्राधिकरण ने ऐसे 76 परियोजनाओं की पहचान की है, जिनके प्रमोटरों ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट अभी तक यूपी-रेरा के वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की है.

रेरा नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर के लिए यह अनिवार्य है कि वह हर वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद अपनी परियोजना के खातों का स्वतंत्र ऑडिट कराए और छह माह के भीतर उसकी रिपोर्ट यूपी-रेरा पोर्टल पर अपलोड करे.

चावल, दालों, खाद्य तेलों में साप्ताहिक तेजी, गेहूं नरम

नयी दिल्ली, 28 जून. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल का औसत भाव बढ़ गया. चावल के साथ दालों और खाद्य तेलों में भी तेजी रही. वहीं, गेहूं में मंदी का रुख देखा गया. सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 38 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 3,905 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं पांच रुपये सस्ता हुआ और 2,781 रुपये प्रति क्विंटल रह गया. आटे का भाव नौ रुपये गिरकर 3,255 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा. सप्ताह के दौरान चना दाल की औसत कीमत 47 रुपये और मसूर दाल की 21 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी.

मानसून की प्रगति से तय होगी बाजार की दिशा

मुंबई, 28 जून घरेलू शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह रही गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर वैश्विक कारकों के साथ घरेलू स्तर पर जारी होने वाले औद्योगिक आंकड़ों और मानसून की प्रगति पर रहे.

अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम शांति समझौते की दिशा में प्रगति का सीधा असर शेयर बाजार पर दिखेगा. साथ ही मानसून की प्रगति भी अहम कारक होगा. मानसून 10 दिन तक अटकने के बाद पश्चिमी भारत में तो आगे बढ़ा है, लेकिन पूर्वी भारत में आगे नहीं बढ़ रहा है. इससे निवेश धारणा पर नकारात्मक असर हो सकता है.

अगले सप्ताह कई महत्वपूर्ण औद्योगिक आंकड़े जारी होने हैं. औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े, पीएमआई के आंकड़े और वाहन कंपनियों के बिक्री के आंकड़े भी निवेशकों के रुख को प्रभावित करेंगे.बीते सप्ताह बीएसई का सेंसेक्स 297.57 अंक (0.39 प्रतिशत) चढ़कर 77,100.47 अंक पर पहुंच गया.

समाचार विशेष

राजनीति के टर्निंग प्वाइंट पर तेजस्वी

सियासी गणित पलटने का मौका, क्या कर पाएंगे?

पटना. भोजपुर में भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर के बाद बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और चार पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी हुई है. हालांकि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है और पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है. यही कारण है कि यह मामला अब केवल एक एनकाउंटर तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा बन गया है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सुशासन और कानून-व्यवस्था के दावों पर जहां अपनों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के लिए यह पूरा घटनाक्रम बिहार की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की राह पर बढ़ने का एक बड़ा और रणनीतिक मौका बनता दिख रहा है.

राजनीति के जानकार इस मामले को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं. वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार शर्मा का मानना है कि यह एनकाउंटर कांड केवल एक कानून-व्यवस्था का मामला नहीं रह गया है, बल्कि यह तेजस्वी यादव की 'ए टू जेड' वाली समावेशी राजनीति को जमीन पर उतारने और अपने कोर वोट बैंक से आगे बढ़कर नए सामाजिक समीकरणों को साधने का एक बड़ा राजनीतिक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. सत्ता की ओर बढ़ने का अवसर तब और दिखने लगता है जब यह स्थापित सत्य है कि बिहार की चुनावी बिसात पर तेजस्वी यादव और आरजेडी के पास लगभग 30 से 32 प्रतिशत वोटों का एक बेहद मजबूत और पारंपरिक आधार पहले से ही मौजूद है.

> **कानून-व्यवस्था का व्यापक सवाल**
>
> तेजस्वी यादव के लिए यह एक बड़ा अवसर इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को केवल एक जाति के नजरिए से नहीं देखा जा रहा. सोशल मीडिया, नागरिक संगठनों और कई राजनीतिक दलों ने इसे पुलिस जवाबदेही, मानवाधिकार और न्यायिक प्रक्रिया से जोड़कर उठाया है .यदि विपक्ष इस मुद्दे को 'हर नागरिक की सुरक्षा' और 'कानून के समान शासन' के रूप में स्थापित करता है, तो इसका दायरा किसी एक समुदाय से आगे बढ़ सकता है.

आप को रोकने के लिए लड़ेगी कांग्रेस

नई दिल्ली. कांग्रेस पार्टी ने अगले साल होने वाले चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है. अभी कांग्रेस दो तरह की रणनीति पर काम कर रही है. पहली रणनीति तो उन राज्यों की है, जहां उसे सफलता की संभावना दिख रही है.

इस लिहाज से उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर को लेकर उसकी तैयारी शुरू हुई है. दूसरी रणनीति आम आदमी पार्टी से लड़ने की है. कांग्रेस के सामने अगले साल के चुनाव के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी की है. पंजाब, गोवा और गुजरात में अगले साल के चुनाव में कांग्रेस की योजना अरविंद केजरीवाल की पार्टी को रोकने की है. ध्यान रहे 2022 में इन तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था. कांग्रेस ने सबसे पहले पंजाब में अपनी रणनीति तय करने का फैसला किया. इसके लिए अजय माकन को पंजाब भेजा गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान को सौंप दी है. अब फैसला होना है. पार्टी किसी जाट सिख को चेहरा बनाए या दलित चेहरा आगे किया जाए इस पर मंथन हो रहा है. आप नेता और मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ अकाल तख्त के फैसले ने कांग्रेस के लिए एक संभावना बनाई है. कांग्रेस उसका लाभ लेना चाहती है.

गोरहे, कायंदे, गवली या नए चेहरे पर दांव

मुंबई. महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति का चुनाव अगले सप्ताह हो सकता है. विधान परिषद चुनाव के बाद सदन में संख्या बल का गणित बदल गया है, इसलिए यह पद एकनाथ शिंदे के खाते में जाता है या नहीं, इस पर सबकी नजर है. विधान परिषद की उपसभापति पद पर शिंदे सेना की नीलम गोरहे है जो पिछले कई सालों से विधान परिषद सदस्य है.

शिंदे सेना के एक नेता ने बताया कि गठबंधन धर्म के अनुसार यह पद शिंदे सेना के पास आना चाहिए. क्योंकि बीजेपी के राम शिंदे सभापति की जिम्मेदारी निभा रहे है, इसलिए उप सभापति का पद हमें मिलना चाहिए. हालांकि उन्होंने आशंका जताई कि बीजेपी अंतिम समय में कुछ भी कर सकती है इसलिए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस पर बारीक नजर है. सूत्रों का कहना है कि उपसभापति का पद शिंदे सेना को मिलने के बाद यह तय नहीं है कि नीलम गोरहे को ही दिया जाए.

पार्टी नए चेहरे पर भी दांव लगा सकती है. इसमें मुंबई से मनीषा कायंदे और यवतमाल-वाशिम की भावना गवली का नाम शामिल है. मनीषा कायंदे को पार्टी का तेज तर्रार नेता माना जाता है, मुंबई में पार्टी की बात पुरजोर तरीके से रखने के लिए वह जानी जाती है. वहीं भावना गवली पूर्व सांसद हैं. सांसद के रूप में उनके पास काम करने का लंबा अनुभव है. उद्धव गुट छोड़कर जब वह एकनाथ शिंदे के साथ आई थी तब कहा गया था कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी. शिवसेना नेता नीलम गोरहे विधान परिषद में डेप्युटी स्पीकर के तौर पर काम कर रही है. वह पिछले कई सालों से शिवसेना का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. वह राज्य में महिलाओं के मुद्दें पर लगातार अपनी आवाज उठाती है.

नीलम गोरहे कौन?

नीलम गोरहे को पार्टी की ओर से दोबारा एमएलसी चुना गया है . चूंकि विधानसभा के उप-अध्यक्ष का पद एनसीपी के पास है, इसलिए उम्मीद है कि परिषद के उप-सभापति का पद शिवसेना को मिलेगा और गोरहे का नाम तय माना जा रहा है . शिवसेना नेताओं का कहना है कि वह मौजूदा उप-सभापति और एक अनुभवी सदस्य हैं, इसलिए उन्हें ही प्राथमिकता दी जा रही है . 2002 में पहली बार चुने जाने के बाद से नीलम गोरहे का यह पांचवां एमएलसी कार्यकाल है . वह महिलाओं की सुरक्षा के लिए राज्य के कानून बनाने में अपने काम के लिए जानी जाती हैं .

विशेष | निशांत को फ्रंट पर लाने का क्या है मकसद

जदयू में सिर्फ एक ही बॉस रहेगा

पटना. गुटबाजी के शिकार हो चली जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की राजनीति में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार एक उम्मीद बन कर उभरे हैं, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता.

पिछले कुछ दिनों की ही बात करें तो नीतीश कुमार का विकल्प कौन पूछे जाने पर जदयू के भीतर से ही कोई पुख्ता आवाज नहीं आती दिखती थी. यह तो बीजेपी के बढ़ते दबदबे का कमाल कहें कि उसकी राजनीति को नियंत्रित करने या नीतीश कुमार की गंगा जमुनी संस्कृति को धार देने के लिए बहुत ही मेहनत के बाद निशांत कुमार का आगमन काफी किन्तु परंतु के बाद हुआ. यूं ही नहीं निशांत कुमार जदयू के भविष्य के रूप में प्रोजेक्ट किए जाने लगे. चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से कारण है.

जदयू के भविष्य के रूप में निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जाना एक राजनीतिक जरूरत और राजनीतिक मजबूरी भी है. अगर निशांत कुमार को राजनीति के प्रति थोड़ी भी रुचि होती तो वे स्वत: जदयू के विकल्प के रूप में चित्रित किए जाते. पर अध्यात्म से नजदीकी और राजनीति से दूरी के कारण निशांत कुमार को समझाना पड़ा. जदयू सूत्रों के अनुसार निशांत कुमार का राजनीति में आने के पीछे का सबसे बड़ा कारण रहा कि विकास की वह ऊंचाई बिहार ने प्राप्त नहीं की, जिस ऊंचाई पर नीतीश ले जाना चाहते थे. पांच साल की सत्ता से विमुख होने के बाद खुद नीतीश कुमार ने भी कहा कि अगले पांच सालों में बिहार विकसित राज्य बन जाएगा. जब निशांत कुमार ने राजनीति में हाथ पांव मारना शुरू कर दिया था, तब उनके बोल भी यही थे कि पिता जी के अधूरे काम को पूरा करना है. मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने जब बतौर राज्यसभा सदस्य दिल्ली का रुख किया तो जदयू के भीतर गुटबाजी चरम पर थी. जदयू कार्यालय में जदयू के वरीय नेताओं के विरुद काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया. कार्यालय में काफी तोड़ फोड़ हुई. खाने के प्लेट, कुर्सी, टेबल तोड़ दिये गए. ऐसे में नीतीश कुमार के साथ भूंजा पार्टी के नाम पर जितने जदयू नेता थे, उनके विरुद्ध पिछड़ों की राजनीति इतनी सक्रिय हो गई कि पार्टी के भीतर लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे. इसी बीच जदयू के भीतर पिछड़ी जाति की राजनीति बन कर जो भी नेता सामने आए, सबों ने निशांत कुमार के राजनीति में आने की पैरवी की. इस बीच में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हों या केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, कुछ अन्य सवर्ण नेताओं ने भी निशांत कुमार को जदयू का भविष्य बताना शुरू किया.

> **नेता पुत्र और गोलबंदी**
>
> इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आगामी राजनीति नेता पुत्र और उनकी गोलबंदी पर आधारित कमो या ज्यादा तो होगी ही . आज राजनीति के दरवाजे पर नेता पुत्रों की बात करें तो राजद सुप्रीमो की विरासत तेजस्वी यदव, रामविलास पासवान की विरासत चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की विरासत दीपक प्रकाश संभालने जा रहे हैं . वैसे में निशांत कुमार जदयू के भविष्य के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं तो उसके पीछे एक मात्र मकसद है कि परोक्ष या अपरोक्ष रूप से नीतीश कुमार का साया या यूं कहें कि छवि छुष्ठ से जुड़ी रहे .